पर्यावरण के नाम पर फिर होने वाली है जनता की ऐसी-तैसी बसों की संख्या घटेगी, जनरेटरों पर पाबंदी होगी

फ़रीदाबाद (म.मो.) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए हरियाणा सरकार ने पहली अक्टूबर से अपनी अनेक बसों का परिचालन बंद कर दिया है। जो बसें बीएस 6 मानक की नहीं होगी वे दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगी।.

फरीदाबाद डीपो में ऐसी 20 बसें हैं जो दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़, अमृतसर, रोहतक, हिसार आदि जाया करती थी, वे अब नहीं जायेंगी। इसी तरह गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत आदि डीपुओं की बसें भी दिल्ली प्रवेश नहीं कर पायेंगी। इनकी कुल संख्या सैंकड़ों में बनेगी।

उक्त डीपुओं के अलावा हरियाणा के तमाम डीपुओं से जो बसें चलकर दिल्ली आया करती थी उनमें से भी वे सभी बसें अब दिल्ली नहीं आ पायेंगी जो बीएस 6 मानक न होंगी। यह घोषणा करने में सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन सरकार ने बीते दो साल में यह कतई सोचने की जरूरत नहीं समझी कि जिस परिवहन व्यवस्था पर सरकार का एकाधिकार है, उसके बंद होने पर यात्री कहां जायेंगे? विदित है कि कोरोना के नाम पर बंद की गई रेलगाड़ियों में से अभी तक आधी भी दोबारा नहीं चल पाई हैं। ऐसे में यात्रियों के साथ क्या बीतेगी यह सवाल भाजपा सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया है।

पर्यावरण के नाम पर थम गयी बसे

दूसरा बड़ा काम डीजल जनरेटर सेट चलाने पर पाबंदी रहेगी। आदेश के अनुसार तो घरेलू जनरेटर भी नहीं चलेंगे। लेकिन वास्तव में यह पाबंदी औद्योगिक जनरेटरों पर भारी पड़ने वाली है। सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति डीजल जनरेटर सेट चलाकर राजी नहीं है। इसका चलाना बहुत ही महंगा पड़ता है। केवल मजबूरी में इसे चलाना पड़ता है और इसके चलते ही सरकारी गिद्ध कारखानेदार पर टूट पड़ते हैं। सरकार यदि वास्तव में ही जनरेटर बंद कराना चाहती है तो वह बिजली की पर्याप्त आपूर्ति क्यों नहीं सुनिश्चित करती?

सुधी पाठक भूले नहीं होंगे जब पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया के इंजीनियरों के सामने लम्बी-लम्बी छोड़ते हुए कहा था कि भारत में बिजली उत्पादन इतना अधिक बढ गया है कि इसे विदेशों तक निर्यात करना पड़ता है। यदि मंत्री महोदय झूठ नहीं बोल रहे थे तो उद्योगों को इतनी बिजली सप्लाइ करें कि उन्हें जनरेटर में डीजल न फुकना पड़े।

उद्योगों पर जनरेटर की पाबंदी के अलावा बॉयलर में लकड़ी, कोयला आदि जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्हें इसके स्थान पर केवल गैस का इस्तेमाल करना होगा। अच्छी बात है गैस का इस्तेमाल होना चाहिये लेकिन सरकार को गैस के दाम भी तो एक उचित सीमा में बांध कर रखने चाहिये। अडानी का जब दिल चाहता है तो दाम बढ़ा देता है।

पर्यावरण के नाम पर सरकार जनता पर तो धड़ाधड़ पाबंदियां थोपने पर जुटी है जबकि उसके अपने निकाय इन नियमों की खुली अवहेलना करते हैं। पूरे एनसीआर में जगह-जगह कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, टूटी सड़कों से धूल के गुबार उठ कर वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, उन्हें कोई पुछने वाला नहीं। जगह-जगह उफनते सीवर नाकाम हो चुके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सरकार को कतई नजर नहीं आते। खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत।

खट्टर सरकार ने एमबीबीएस की फीस बढ़ाई

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा में 6 सरकारी मेडिकल कालेज हैं जिनमें 810 के लगभग एमबीबीएस की सीट हैं और 260 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट हैं । हाल ही में हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस के 2020 के दाखिलों वाले विद्यार्थियों से 10 लाख में से फीस निकल कर बैंक लोन गारंटी बांड प्रति वर्ष 4 साल तक देने की चिट्ठी एक बार फिर पिछले हफ्ते निकाली बताई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एमबीबीएस की कुल फीस बांड गारंटी को मिलाकर और इस पर बैंक के ब्याज को मिलाकर 52 लाख के आस पास हो गयी है।

साफ है सरकार की नीयत कि वह हरियाणा के गरीब परिवारों के बच्चों को डॉक्टर नहीं बनने देना चाहती। बताएं आप कौन इतना खर्च करके अपने बच्चे को डॉक्टर बना पायेगा?

सरकार का कहना है कि छात्र एमबीबीएस करने के बाद यदि वह हरियाणा सरकार की नौकरी जॉइन करता है तो तनखा के साथ साथ इस बैंक लोन की वापसी भी सरकार करेगी। यदि वह सरकारी नौकरी नहीं जॉइन करता तो उसे पूरा लोन 7 साल में वापस करना होगा। साथ ही सरकार यह भी कह रही है कि वह सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं करती। 800 डॉक्टर हर साल पास आउट होंगे और सभी सरकारी नौकरी जॉइन करना चाहें तो क्या सरकार सभी की हर साल इतनी नौकरी देने की क्षमता रखती है?

यदि नहीं तो फिर बांड का पैसा नौकरी जॉइन करने पर सरकार द्वारा वापिस करने का क्या मायने रखता है? मैं सरकार से नौकरी मांगता हूं और सरकार नौकरी नहीं दे रही तो मेरे से बांड के पैसे की वापसी क्यों? गम्भीर मसला है।

पीजीआईएमएस रोहतक में छात्र इकट्ठे होकर डीन के पास गए और नाराजगी के साथ बता कर आये हैं कि हम बांड नहीं भरेंगे।

आम जन से भी उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि उनके अपने स्वास्थ्य और इलाज का मामला इस मामले के साथ साफतौर पर जुड़ा हुआ है , इसलिए इस मसले पर छात्रों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हों।

खट्टर सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि उसे आम जनता को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई रुचि नहीं है। पहले से ही लचर सेवाओं को और भी लचर बनाने में उनका यह कदम और भी बढ़ावा देगा। समझने वाली बात है कि जो छात्र डिग्री लेकर 52 लाख कर्जे के साथ बाहर आयेगा वह अपने मरीजों को कैसी सेवाएं दे पायेगा। नौकरी से मिलने वाले वेतन से वह अपनी गुजर-बसर करेगा या कर्जे और उसका ब्याज उतारेगा? जाहिर है ऐसे में मरीजों की गर्दन और जेबें ही काटेगा।

विरोधी भी मानते हैं कि अपना सबसे बड़ा सेल्समैन वह खुद है

विष्णु नागर

ये तो उसके बड़े से बड़े विरोधी भी मानते हैं कि अपना सबसे बड़ा सेल्समैन वह खुद है। वह कुछ भी बेच सकता है! ।जो है,वह भी और जो नहीं है, वह भी !सड़क पर पड़ा धूलभरा पत्थर भी वो इतनी खूबसूरती से बेच लेता है,जितनी खूबसूरती से हीरा व्यापारी हीरा भी नहीं बेच सकता!

टूटी हुई ईंट को सोने के भाव बेचना भी उसे आता है और सोने को, टूटी ईंट के भाव बेचना भी !इस आदमी ने तय किया कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3.20 किलोमीटर लंबी सड़क की कथित खूबसूरती को बेचना है। मनमोहन सिंह के बस में यह नहीं था ।वे अर्थशास्त्री थे, उनके खून में व्यापार नहीं था ।मान लो,वह इस सुंदर सड़क का भी सौंदर्यीकरण करवाते तो हद से हद अपने किसी मंत्री से कहते कि भाईसाहब या बहनजी,आप ही उद्घाटन कर दो या मत करो, कौनसा बड़ा तीर हमने मारा है,छोड़ो! इतना जरूर करो कि इसका दिल्ली - हरियाणा-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखबारों में विज्ञापन छपवा दो, इतना काफ़ी है । इसके विपरीत इस आदमी ने इतनी मामूली चीज़ की भी बढ़िया पैकेजिंग की और 'विकास पुरुष' का धंधा चमका लिया !बीच में यह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को भी ले आया। उनकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया।

साथ में यह झूठ भी बोल दिया कि जार्ज पंचम के निशान को मिटाकर नेताजी की प्रतिमा लगाई है,जैसे यहां इससे पहले शहीदों की स्मृति में अमर जवान ज्योति नहीं जल रही थी,जिसे चुपके से इसी ने हटवाया था !अमर जवान ज्योति को हटवाया और झूठ- मूठ में गुलामी का प्रतीक हटाने का श्रेय भी ले लिया !इस तरह हो गई 'नये भारत' की प्राणप्रतिष्ठा! सीधे बंबइया फिल्म का फार्मूला है !यह फार्मूला फिल्मों में तो पिट रहा है, राजनीति में भी कितना चलेगा! इनका हीरो अक्षय कुमार पिट गया तो राजनीति का अक्षय कुमार भी कब तक चलेगा!

इस आदमी को हरेक के आदर्शों पर चलने, उनके सपनों का भारत बनाने का अभ्यास है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर भगत सिंह, गुरु गोलवलकर से लेकर बाबा बासाहेब अंबेडकर तक के आदर्शों पर चलना आसानी से जानता है ।कई बार दिन में दो बार, तीन बार भी इसके- उसके सपनों का भारत बनाकर धर देता है!पिछले आठ सालों में यह शख्स सैकड़ों महापुरुषों के सपनों को साकार कर चुका है और सैकड़ों को महापुरुष भी बना चुका है! ज़ुबान ही तो हिलाना है! शब्दों की चाशनी ही तो बनाना है! एक दिन नेताजी के आदर्शों पर भी चल देना इसके लिए कौनसा बड़ी बात है!इस बहाने किसी न किसी को नीचा दिखाने का सुख भी मिल जाता है!

तो ये हुआ पैकेजिंग भाग-1 ।अब बात राजपथ के सौंदर्यीकरण को बेचने की ।कुल 3.20 किलोमीटर की सड़क की सुंदरता को इसे बेचना था! ।ऐसा नहीं हो सकता था कि यह कहता कि मेरी सरकार यानी मैंने, राजपथ को कितना सुंदर बनवा दिया है ।मोदी -ब्रांड इससे नहीं बनता! इसलिए राजपथ का नाम बदला जाता है ।इस नाम को गुलामी का प्रतीक बताया जाता है !इसे कर्तव्य पथ नाम दिया जाता है ।और कर्तव्य किसका? जनता के अलावा कर्तव्य कौन निबाह सकता है !राजा का कर्तव्य तो राज करना है,सो अरबों के हवाई जहाज,12 करोड़ की कार से धरा को रौंदते हुए,दो लाख की घड़ी और 1.30 लाख की कलम धारण कर राजा जी निभा रहे हैं !इस सड़क और इसके आसपास की बिल्डिंगों में रहेंगे ये।

खाएंगे ये, खिलाएंगे ये ।अपना शानदार बंगला बनवाएंगे ये। दिन में छह बार कपड़े बदलेंगे ये। सुविधाओं के गुलामी करेंगे ये। अंदाज़ शाही दिखाएंगे ये ।अमीर देशों के गोरे प्रमुखों से मिलेंगे तो गले ऐसे लगाएंगे,जैसे ये उनके बचपन के दोस्त हों!

मन और मानस से गुलामी करेंगे ये और गुलामी के प्रतीकों से लड़ेंगे भी ये ,जो सिर्फ अपनी गद्दी के लिए लड़ना जानते हैं! अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने के लिए बरसों जेल में काटने वाले, प्रधानमंत्री होकर भी खटारा पंखे के नीचे सोनेवाले, नेहरू जी तो गुलामी की मानसिकता का शिकार थे और ये आजादी की मानसिकता के शिकार हैं !और अभी तो टुकड़ों-टुकड़ों में ये पूरा सेंट्रल विस्टा बेचेंगे!

2024 तक इसी तरह धंधा चमकाएंगे। ये ही इनके लिए न्यू इंडिया बनाना है!इसी तरह इन्होंने आज तक सब मिटाया है!